
	केन्द्रीय कर आयुक्त (अपील)		
	O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), CENTRAL TAX, वस्तु एवं सेवा कर भवन सातवीं मंजिल पॉलिटेक्निक के पास, आम्बावाडी, अहमदाबाद-380015		
	GST Building-7 th Floor, Near Polytechnic, Ambavadi, Ahmedabad- 380015		
 079-26305065			टैलेफैक्स : 079-26305136

क फाइल संख्या : File No : V2/40/RA/GNR/2018-19 | 10321 to 10325
 ख अपील आदेश संख्या : Order-In-Appeal No.: AHM-EXCUS-003-APP-189-18-19
 दिनांक Date : 14-03-2019 जारी करने की तारीख Date of Issue: 06/05/2019

श्री उमाशंकर आयुक्त (अपील) द्वारा पारित

Passed by **Shri Uma Shanker** Commissioner (Appeals) Ahmedabad

ग अपर आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद-III आयुक्तालय द्वारा जारी मूल आदेश : 18/AC/CGST/2018-19
 दिनांक : 25-05-2018 से सृजित

Arising out of Order-in-Original: 18/AC/CGST/2018-19, Date: 25-05-2018 Issued by:
 Assistant Commissioner, CGST, Div:Kadi, Gandhinagar Commissionerate, Ahmedabad.

घ अपीलकर्ता एवं प्रतिवादी का नाम एवं पता

Name & Address of the **Appellant** & Respondent

M/s. Zorex Pharma Pvt. Ltd

कोई व्यक्ति इस अपील आदेश से असंतोष अनुभव करता है तो वह इस आदेश के प्रति यथास्थिति नीचे बताए गए सक्षम अधिकारी को अपील या पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

I. Any person aggrieved by this Order-In-Appeal issued under the Central Excise Act 1944, may file an appeal or revision application, as the one may be against such order, to the appropriate authority in the following way :

भारत सरकार का पुनरीक्षण आवेदन :
Revision application to Government of India :

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा अंतर्गत नीचे बताए गए मामलों के बारे में पूर्वोक्त धारा को उप-धारा के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन अवर सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली : 110001 को की जानी चाहिए।

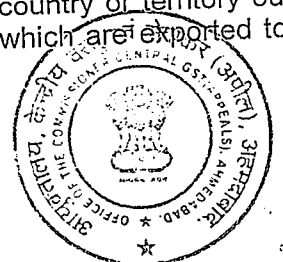
(i) A revision application lies to the Under Secretary, to the Govt. of India, Revision Application Unit Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi - 110 001 under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35 ibid :

(ii) यदि माल की हानि के मामले में जब ऐसी हानि कारखाने से किसी भण्डागार या अन्य कारखाने में या किसी भण्डागार से दूसरे भण्डागार में माल ले जाते हुए मार्ग में, या किसी भण्डागार या भण्डार में चाहे वह किसी कारखाने में या किसी भण्डागार में हो माल की प्रक्रिया के दौरान हुई हो।

(ii) In case of any loss of goods where the loss occur in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse.

(ख) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित माल पर या माल के विनिर्माण में उपयोग शुल्क कच्चे माल पर उत्पादन शुल्क के रिबेट के मामलों में जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित है।

(b) In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.



- (ग) यदि शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर (नेपाल या भूटान को) निर्यात किया गया माल हो।
 (c) In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

ध अंतिम उत्पादन की उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडिट मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो इस धारा एवं नियम के मुताबिक आयुक्त, अपील के द्वारा पारित वो समय पर या बाद में वित्त अधिनियम (नं.2) 1998 धारा 109 द्वारा नियुक्त किए गए हो।

(d) Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under and such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec.109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रपत्र संख्या इए-8 में दो प्रतियों में, प्रेषित आदेश के प्रति आदेश प्रेषित दिनांक से तीन मास के भीतर मूल-आदेश एवं अपील आदेश की दो-दो प्रतियों के साथ उचित आवेदन किया जाना चाहिए। उसके साथ खाता इ. का मुख्यशीर्ष के अंतर्गत धारा 35-इ में निर्धारित फी के भुगतान के सबूत के साथ टीआर-6 चालान की प्रति भी होनी चाहिए।

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(2) रिविजन आवेदन के साथ जहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- फीस भुगतान की जाए और जहाँ संलग्न रकम एक लाख से ज्यादा हो तो 1000/- की फीस भुगतान की जाए।
 The revision application shall be accompanied by a fee of Rs.200/- where the amount involved is Rupees One Lac or less and Rs.1,000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील:-
 Appeal to Custom, Excise, & Service Tax Appellate Tribunal.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35- णबी/35-इ के अंतर्गत:-

Under Section 35B/ 35E of CEA, 1944 an appeal lies to :-

उक्तलिखित परिच्छेद 2 (1) क में बताए अनुसार के अलावा की अपील, अपीलो के मामले में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, अहमदाबाद में दूसरा मंजिल, बहूमाली भवन, असारवा, अहमदाबाद, गुजरात 380016

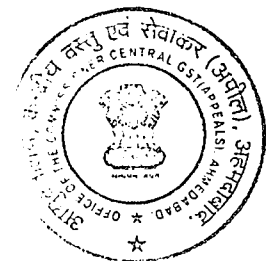
To the west regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at 2nd floor, Bahumali Bhavan, Asarwa, Ahmedabad-380016 in case of appeals other than as mentioned in para-2(i) (a) above.

(2) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 की धारा 6 के अंतर्गत प्रपत्र इए-3 में निर्धारित किए अनुसार अपीलीय न्यायाधिकरणों की गई अपील के विरुद्ध अपील किए गए आदेश की चार प्रतियाँ सहित जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या उससे कम है वहां रूपए 1000/- फीस भेजनी होगी। जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या 50 लाख तक हो तो रूपए 5000/- फीस भेजनी होगी। जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना रूपए 50 लाख या उससे ज्यादा है वहां रूपए 10000/- फीस भेजनी होगी। की फीस सहायक रजिस्टार के नाम से रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के रूप में संबंध की जाये। यह ड्राफ्ट उस स्थान के किसी नामित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की शाखा का हो

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 as prescribed under Rule 6 of Central Excise(Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against (one which at least should be accompanied by a fee of Rs.1,000/-, Rs.5,000/- and Rs.10,000/- where amount of duty / penalty / demand / refund is upto 5 Lac, 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asstt. Registrar of a branch of any nominate public sector bank of the place where the bench of any nominate public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated

(3) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश होता है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए फीस का भुगतान उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिए इस तथ्य के होते हुए भी कि लिखा पढी कार्य से बचने के लिए यथार्थिती अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है।

In case of the order covers a number of order-in-Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner not withstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lacs fee of Rs.100/- for each.



(4) न्यायालय शुल्क अधिनियम 1970 यथा संशोधित की अनुसूची-1 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार उक्त आवेदन या मूल आदेश यथास्थिति निर्णयन प्राधिकारी के आदेश में से प्रत्येक की एक प्रति पर रु.6.50 पैसे का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।

One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjournment authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 paisa as prescribed under scheduled-I item of the court fee Act, 1975 as amended.

(5) इन ओर संबंधित मामलों को नियंत्रण करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्याविधि) नियम, 1982 में निहित है।

Attention is invited to the rules covering these and other related matter contended in the Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

(6) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सीस्टेट) के प्रति अपीलों के मामलों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1984 की धारा 34फ के अंतर्गत वित्तीय(संख्या-2) अधिनियम 2014(2014) की संख्या 24) दिनांक: 06.08.2014 जो की वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, द्वारा निश्चित की गई पूर्व-राशि जमा करना अनिवार्य है, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत जमा की जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रूपए से अधिक न हो

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत " माँग किए गए शुल्क " में निम्न शामिल हैं

- (i) धारा 11 डी के अंतर्गत निर्धारित रकम
- (ii) सेनवैट जमा की ली गई गलत राशि
- (iii) सेनवैट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम

→ आगे बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (सं. 2) अधिनियम, 2014 के आरम्भ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थगन अर्ज़ी एवं अपील को लागू नहीं होंगे।

For an appeal to be filed before the CESTAT, it is mandatory to pre-deposit an amount specified under the Finance (No. 2) Act, 2014 (No. 25 of 2014) dated 06.08.2014, under section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under section 83 of the Finance Act, 1994 provided the amount of pre-deposit payable would be subject to ceiling of Rs. Ten Crores,
Under Central Excise and Service Tax, "Duty demanded" shall include:

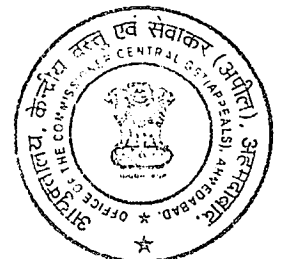
- (i) amount determined under Section 11 D;
- (ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules.

→ Provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

(6)(i) इस आदेश के प्रति अपील प्राधिकरण के समक्ष जहाँ शुल्क अथवा शुल्क या दण्ड विवादित हो तो माँग किए गए शुल्क के 10% भुगतान पर और जहाँ केवल दण्ड विवादित हो तब दण्ड के 10% भुगतान पर की जा सकती है।

(6)(i) In view of above, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute."

II. Any person aggrieved by an Order-in-Appeal issued under the Central Goods and Services Tax Act, 2017/Integrated Goods and Services Tax Act, 2017/Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017, may file an appeal before the appropriate authority.

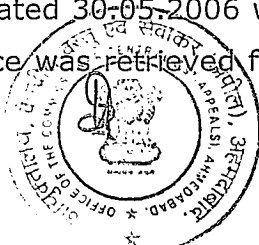


ORDER-IN-APPEAL

This appeal has been by the Assistant Commissioner of CGST, Kalol Division [hereinafter referred to as "the department"] against the Order-in-Original No.18/AC/CGST/18-19 dated 25.05.2018 (*hereinafter referred to as "the impugned order"*) passed by the Assistant Commissioner of Central GST, Kadi Division, Gandhinagar (*hereinafter referred to as "the adjudicating authority"*) in respect of M/s Zorex Pharma Pvt Ltd, Plot No.858, Kothari Estate, Santej, Ta-Kalol, Dist Gandhinagar (*hereinafter referred to as 'the appellant'*) as per Review Order No.27/208-19 dated 08.10.2018 of the Commissioner of CGST, Gandhinagar Commissionerate.

2. Briefly stated, the respondent was engaged in the manufacture of P.P. Medicines falling under chapter sub-heading 3003 of the first schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (CETA, 1985). They were availing value based SSI exemption up to clearance value of Rs.150 Lakhs under Notification No. 08/2003 dated 01/03/2003 (as amended) (*hereinafter referred to as the 'SSI notification'*) for clearance of its own goods, whereas the goods manufactured for loan licensees under various brand names not belonging to the appellant, was cleared on payment of Central Excise duty @ 16% from the first clearance in a financial year. The factory of the appellant was falling within '**rural area**', as defined in paragraph 4 of the SSI notification. The exemption contained in the SSI notification did not apply to specified goods bearing a brand name or trade name whether registered or not, of another person, except in cases where such branded specified goods were manufactured in a factory located in a '**rural area**'. It appeared that the appellant was liable to take into account also the value of branded goods for the purpose of determining the exemption limit of aggregate of first clearance value not exceeding 150 Lakhs Rupees made on or after 1st April in a financial year and also for the purpose of determining the aggregate value of clearances of all excisable goods for home consumption by a manufacturer from one or more factories, or from a factory by one or more manufacturers not exceeding 400 Lakhs Rupees in the preceding financial year. As the appellant had failed to add the value of branded goods for the purpose of determining the said aggregate values of clearances in a financial year as well as the preceding financial year, a show cause notice dated 30.05.2006, covering the period from 2001-02 to 2005-06, for denying the benefit of SSI notification and demanding Rs.39,91,757/- with interest and also proposes imposition of penalty under Section 11 AC of the Central Excise Act, 1944 was issued.

2.1 Meanwhile, in an identical matter in respect of M/s Rhombus Pharma Pvt Ltd, Commissioner, Central Excise, Ahmedabad-II, vide OIO dated 20.04.2007 had dropped the proceedings initiated by show cause notices as time barred as no suppression was proved. Since the department has filed an appeal before CESTAT, the above said show cause notice dated 30-05-2006 was transferred into call book. However, the said show cause notice was retrieved from call book on 28.09.2009.



The CESTAT, vide order No.A/11397-11397/2015 dated 08.10.2015 has rejected the department appeal and concluded that the demand of duty for the extended period of limitation cannot be sustained and uphold the duty with interest for the normal period of limitation.

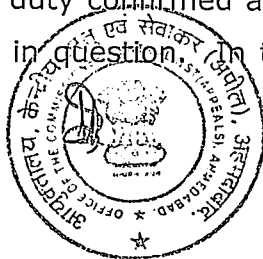
2.2 In view of above referred CESTAT's order and CESTAT's order No.A/1330134/2009 dated 07.01.2009, in case of Pharmanza India, wherein it has held that the duty already paid on branded goods are required to be adjusted against the duty demanded from the assessee and directed for re-quantification of such duty, the adjudicating authority has decided the show cause notice dated 30.05.2006, vide impugned order, by dropping the demand of Rs.31,73,189/- pertaining to beyond normal period as time barred and confirmed the demand of Rs.8,18,568/-with interest falling within normal period. He also adjusted duty amounting to Rs.2,54,279/- against the duty confirmed. A penalty of Rs.50,000/- each was also imposed against the respondent.

3. The department has filed the instant appeal mainly on the grounds that the adjudicating authority has committed error in re-quantification of the demand in as much as the adjudicating authority has not given any basis on which the said demand has been re-quantified; that the impugned order does not contain any detailed calculation for the amount confirmed and adjusted and serve to be remanded back to the adjudicating authority with a direction to go through the entire records and decide the issue afresh.

3. Personal hearing in the appeal was held on 07.03.2019. Shri Viral Shah, Ddirector and Shri Chirag Shah, Accountant of the respondent appeared for the same and explained the case.

6. At the outset, I find that the adjudicating authority has decided the instant issue on the basis of the Hon'ble CESTAT's order No.A/11396-11397/2015 dated 08.10.2015 in respect of M/s Rhombus Pharma Pvt Ltd and also decision of M/s Pharmanza India reported in 2009 (237) ELT 488. In the case of M/s Rhombus Pharma Pvt Lt, it has been concluded that the demand of duty for the extended period of limitation cannot be sustained and only the demand for the normal period of limitation is sustainable. In the case of M/s Pharmanza India, the Hon'ble Tribunal has held that the duty already paid on goods cleared by the loan licensee is required to be adjusted against the duty demand.

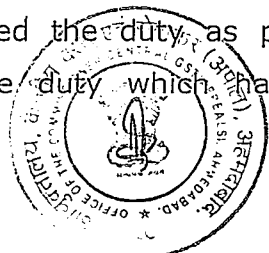
7. I find that the respondent had filed an appeal against the same impugned order, vide appeal No.151/GNR/18-19 and the said appeal was decided by me by way of remand, vide OIA No.AHM-EXCUS-003-APP-177-18-19 dated 29.01.2019, with a direction to re-calculate the duty confirmed and adjust the duty accordingly against the demand for the period in question. In the said OIA, it has been held that:



"7. In this case, as stated above, the respondent was availing value based SSI exemption up to clearance value of Rs.100 Lakhs under Notification No. 08/2003 dated 01/03/2003 (as amended) for clearance of its own goods, whereas the goods manufactured for loan licensees under various brand names not belonging to the appellant, was cleared on payment of Central Excise duty @ 16% from the first clearance in a financial year. The Hon'ble CESTAT has clearly held that *"the demand of duty for the extended period of limitation cannot be sustained and only the demand for the normal period of limitation is sustainable"* and *"duty paid on the clearances, which the Revenue has contended to be exempted, should be considered as deposit and the said duty is required to be adjusted against the duty now being demanded from the appellant"* and *such re-quantification exercise is to be done only for the period within limitation.*

8. The impugned order states that the appellant had crossed their threshold exemption limit of one crore rupees on 28.05.2005, while considering their own clearance and clearance value of loan licensees. Therefore, no duty was required to be paid by the appellant upto 28.05.2005 and from 29.05.2005 onwards, they were required to pay duty on their own clearances as well as those of the Loan Licensee. However, the appellant had discharged duty in respect of clearance of Loan Licensee from April 2005 onwards and as per Hon'ble CESTAT's order, the duty which has already been paid on such clearances, which the department has contended to be exempted, should be considered as deposit. In the circumstances, whatever duty has already been paid by the appellant from April 2005 to till crossing the threshold limit should be taken into consideration while adjusting the duty. The appellant has contended that the order of the adjudicating authority is not correct and not as per guidelines of the above referred CESTAT's order. They contended that the adjudicating authority has given adjustment of Rs.2,54,279/- for the clearances from 01.05.2005 to 28.05.2005 and not for the duty paid on clearance from April 2005 onwards. I find merit consideration in the said argument, by following the decision of Hon'ble Tribunal supra.

9. I find that the adjudicating authority has re-quantified the duty vide para 23.13 and 23.15 of the impugned order. He stated that "In the instant case the date of delivery of show cause notice is 08.06.2006 i.e considering the period within limitation for re-quantification is 09.06.2005 to 31.03.2006. The said assessee had filed their mothly ER-1 return for April 2005 on 12.05.2005 i.e not within normal period. and for the month of May on 10.06.2005 i.e within normal period. Thus the discharge of C.Excise duty for the clearance for the period 01.05.2005 to 28.05.2005 pertaining to the loan licensee before attaining 1 crore clearance are required to be adjust while demanding the duty on own clearance...". I find that that the adjudicating authority has not adjusted the duty as per Hon'ble CESTAT's order as discussed above that the duty which has already been paid on such



clearances, which the department has contended to be exempted, should be considered as deposit as discussed at para 8 above and required to be adjusted such payment against the demand. In view of above, I am of the opinion that the matter needs to be verified by the adjudicating authority according to the ratio of the decision of the Hon'ble Tribunal and the duty particulars paid by the appellant as has been observed above. Therefore, I remand the case to the adjudicating authority, in view of foregoing discussions."

10. Further, as regards imposition of penalty, I observe that the adjudicating authority has imposed penalty of Rs.50,000/- under Rule 25 of Central Excise Rules, 2002. Since the issue involved in the appeal is under litigation since 2005, I do not find any merit to impose any penalty in the matter. Therefore, the penalty imposed is set aside."

8. Since the appeal filed by the respondent against the impugned order in question has already been decided by me vide OIA mentioned supra by way remand for re-quantification of duty as per Hon'ble CESTAT's order, the appeal filed by the department is also required to be remanded.

10. In view of above, I allow the appeal filed by the department by way of remand. The appeal stand disposed of in above terms.

उमाशंकर

(उमा शंकर)

प्रधान आयुक्त (अपील्स)

Date : .3.2019

Attested

Mohan V.V.
(Mohan V.V)
Superintendent (Appeal)
Central Excise, Ahmedabad

BY R.P.A.D.

To,
M/s Zorex Pharma Pvt Ltd,
Plot No.858, Kothari Estate, Santej, Ta-Kalol,
Dist Gandhinagar

The Assistant Commissioner of CGST
Division- Kalol.

Copy to:

1. The Chief Commissioner of Central GST Zone, Ahmedabad.
2. The Commissioner of Central GST, Gandhinagar.
3. The Additional Commissioner(Systems) Central GST, Gandhinagar
4. Guard file
5. P. A.

